

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4428
27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में सीआईटीआईआईएस योजना

†4428. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवाचार, एकीकरण और स्थिरता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस) योजना (1.0 और 2.0) के आरंभ से अब तक आन्ध्र प्रदेश में इसके कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सीआईटीआईआईएस योजना 1.0 और 2.0 के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई कुल निधि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में उक्त योजना के कार्यान्वयन का विस्तार करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने सीआईटीआईआईएस योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) दो शहरों अर्थात् अमरावती और विशाखापत्तनम को 06 मार्च, 2019 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य से सिटी इन्वेस्टमेंट टू सिटी इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सीआईटीआईआईएस) 1.0 कार्यक्रम के अंतर्गत चुना गया था।

सीआईटीआईआईएस 1.0 के अंतर्गत, ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी) द्वारा संचालित 39 स्कूलों को बाल-अनुकूल और सर्वसुलभ इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ उन्नत करने के लिए विशाखापत्तनम शहर को 52 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता आवंटित की गई। कुल राशि स्वीकृत की गई और उसका उपयोग किया गया था।

सीआईटीआईआईएस 1.0 के अंतर्गत, अमरावती शहर को 15 ई-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, 15 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों, 14 प्राथमिक विद्यालयों और 1 बहु-धर्म अंतिम संस्कार परिसर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन के लिए 80 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता आवंटित की गई। जिसमें से 72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे और जिनमें से 66.47 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

सीआईटीआईआईएस 2.0 के तहत, आंध्र प्रदेश उन 21 राज्यों में से एक है, जिन्होंने कार्यक्रम के क्लाइमेट एक्शन घटक के लिए राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) ने 03.03.2025 को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। आंध्र प्रदेश राज्य को 23 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ग) सीआईटीआईआईएस 2.0 कार्यक्रम 31.05.2023 को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु-उन्मुख सुधार कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत सुदृढीकरण और ज्ञान प्रसार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं को व्यापक सहायता प्रदान करना था।

(घ) जी, हां। नियमित क्षमता निर्माण कार्यशालाओं, मीडिया-भागीदारी और प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं जैसी सामुदायिक-मीडिया गतिविधियों के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है।
